reduction in excise duty rate, it may be stated that the excise duty for sugar has already been reduced in successive stages and the internal consumption has been stepped up from 37.5 lakh tonnes to 45 lakh tonnes and the months following decontrol the internal consumption has been ranging from 4.5 to 5.00 lakh tonnes. The consumption in 1978-79 sugar season is estimated to be at least 52 lakh tonnes. But further stimulation of internal consumption by resorting to the reduction of excise duty and consequent fall in prices, while it may be advantageous to the sugar factories, would create serious problems to the khandsari and gur industries which are affected even at the present prices. This point will be examined after a few months after watching how the khandsari and gur industry will fare during this season. As regard relief to the weaker units, it may be stated that this point was examined in depth at the time of decontrol itself and it was felt at that time that no differential help need be given to such units as such an artificial protection would inhibit the units from trying to modernise, expand and rehabilitate themselves which again would in any case be the only real solution in the long run for the betterment of the sugar industry. As regards bank credit. the question of giving clean cash credit of Rs. 25 lakhs and the possibility of obtaining medium term loans to the sugar units is already under examination by the Government. As regards restrictions on the trade, the Government have already liberalized the permissible stock limits by traders by increasing them by 50 per cent over previous limits, and the need for further liberalisation is under examination. However, as regards licensing of sugar dealers, it may be stated that this my be necessary at least in the interest of getting adequate information regarding the sugar transactions. However, at the time of decontrol itself, the State Government have been advised to liberalise the issue of sugar dealers licences.

Demand for full autonomy for Universities

3880. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether he is aware about the demand for full autonomy for Universities both in academic and administrative sphere raised by the National Convention of Teachers of Central Universities which concluded its two-day session at Banaras Hindu University;

(b) what are the resolutions adopted by the Convention; and

(c) what is the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). Information has been received about three declarations prepared at the Central Universities Teachers' Association Meet. These relate to autonomous and democratic functioning of various bodies of the Universities, implementation of a scheme combining the principle of merit and teaching experience for providing next higher grade to teachers and other benefits, besides provision of various other facilities to teachers. No resolution as such has been received by Government.

(c) Government recognise the principle of autonomous and democratic functioning of various bodies of the Univerities. As regards other matters, they lie within the purview of various University authorities to consider and implement.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र

3881, श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1978 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मंगोलपुरी, सुलतानपुरी, ज्वालापुरी,

नांगलोई, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, शकूरपुर, न्यू सीमापुरी, नन्दनगरी आदि में जनता फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और लोगों ने इस प्रयोजनार्थ 200 रुपये की राशि जमा कराई । लेकिन उन्हें अब तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गये है ;

(ख) यदि हां, उनके क्या कारण हैं, और

(ग) उन व्यक्तियों को जिन्होंने 200 रुपये की राशि जमा कराई है, कब तक फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां, लगभग 3100 व्यक्तियों ने अपने आप को पंजीकृत करवाया तथा 1623 व्यक्तियों को अभी तक आवंटन किया गया है शेष व्यक्तियों को निम्नलिखित कारणों से आवंटन नहीं किया जा सका :—

(i) 636 मकान बाढ़ पीड़ितों के पास हैं और इनका आवंटन तभी किया जा सकता है जब कि ये खाली हो जाए ।

(ii) आवेदक कालोनियों को चुनने के बारे में हठी हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग एक महीने में एक विवरणिका जारी करने वाला है, उसके अनुसार सारी औपचारिकता पूरी होने पर 3000 मकानों का आवंटन कर दिया जायेगा ।

चीनी के मूल्य में गिरावट

3882. **श्री रामधारी सिंह शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि चीनी के कारखाना मूल्य घट कर 180 रुपये से 190 रुपये तक हो गये हैं जबकि इसकी औसत लागत 230 रुपये प्रति क्विंटल है;

(ख) क्या यह सच है कि इस गिरावट के कारण चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, और यदि हां, तो किसानों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि यही स्थिति रही तो क्या चीनी उद्योग बन्द होने की स्थिति में नहीं पहुंच जायेगा; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सावधानी-उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : 1977-78 के लिए चीनी की उत्पादन लागत की भारित औसत का जो हिसाब लगाया गया था वह 223/- रुपये प्रति क्विंटल बैठता है । सितम्बर और अक्तूबर, 1978 में फैक्ट्री के द्वार पर प्राप्तियां क्रमशः 197.80 रुपये और 183.61 रुपये प्रति क्विंटल थीं ।

(ख) और (ग) : 15-11-1978 को विभिन्न चीनी मिलों में गन्ने के मूल्यों के बकायों के प्रति 4082.63 लाख रुपयों का भुगतान करना था । किसानों के हितों की सुरक्षा करने तथा उद्योग की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जो पग उठाए गए हैं, उनमें 8.5 प्रतिशत की वसूली पर गन्ने का 10/- रुपये प्रति क्विंटल का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना, जबकि पिछले वर्ष यह मूल्य 8.5 प्रतिशत की वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल था, उद्योग के लिए ऋण संबंधी सुविधाओं को उदार बनाना ताकि वह किसानों के बकायों का भुगतान कर सके, गुड़ के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों की स्टाक रोकने की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना ताकि उद्योग को भारी स्टाक रखने संबंधी भार के बारे में राहत दी जा सके, उत्पादन शुल्क में निरन्तर कमी करने, परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि में ऊंची लागत पर स्थापित की गई नयी फैक्ट्रियों और विस्तार प्रोजेक्टों को राहत देने से संबंधित योजना में संशोधन करना; उत्तर प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये का ऋण देना ताकि उस राज्य में स्थित सरकारी और सहकारी चीनी फैक्ट्रियां किसानों को उनके गन्ने के बकायों का भुगतान कर सके और उन चीनी फैक्ट्रियों के प्रबंध को ग्रहण करने, जिन्होंने गन्ने के मूल्य के बकायों का 10 प्रतिशत से अधिक का भुगतान नहीं किया है अथवा जो समय पर पिराई कार्य शुरु नहीं करती हैं, के लिए एक अध्यादेश जारी करना शामिल है ।

Deterioration in productivity of Exotic Wheat Seed

3883. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any deterioration has been noticed in the productivity of exotic wheat seeds like Kalyan Sonora, Sonalika, Sharbati Sonora etc. introduced in the late 60's; and

(b) if so, whether Government has released the new generation of seeds for rabi sowing; and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): A similar question No. 947 was asked in the